

[2023] 1 एस. सी. आर 1105

/

सुनील सैनी एंड ओआरएस. वी.

हरियाणा और ओआरएस का राज्य।

(2019 की स्थानांतरण याचिका (आपराधिक) No.125) 30 जनवरी, 2023

/

[के. एम. जोसेफ और बी. वी. नागरत्ना]

स्थानांतरण याचिका: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, झज्जर की न्यायालय से मामले को नई दिल्ली अंतर्गत सक्षम न्यायालय अंतर्गत स्थानांतरित करने की मांग-आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा राज्य अंतर्गत जाट समुदाय के आंदोलन के कारण तोड़फोड़ और आगजनी की घटना हुई, जिससे याचिकाकर्ताओं के घरों, गोदामों और उनके हर सामान अंतर्गत कथित रूप से भारी क्षति हुई-विधि और व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई जिसके परिणामस्वरूप भारी नुकसान हुआ- अभियोजन दल निष्पक्ष और निडर तरीके से काम नहीं कर रहा है-याचिकाकर्ता जो गवाह हैं, उन्हें दूसरे पक्ष द्वारा धमकी दी गई है: समय बीतने और इस तथ्य के कारण कि लगभग 42 गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है, मामले को स्थानांतरित नहीं किया जाना है-विशेष लोक अभियोजक को हाल ही में नियुक्त किया गया है और उसकी साख की परवाह किए बिना, जो ध्यान में लाया गया है, इस स्तर पर उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जा सकता है-इसे ध्यान में रखते हुए, याचिका का निपटारा किया गया, जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं के लिए अभियोजन निदेशक से संपर्क करने के लिए यह खुला होगा कि वे मानते हैं कि नियुक्त विशेष लोक अभियोजक भी निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है-निदेशक (अभियोजन) मामले को देखें और उचित कदम उठाएं-जहां तक गवाह की सुरक्षा का संबंध है, याचिकाकर्ताओं के लिए यह खुला होगा कि वे पूर्व सूचना को स्थानांतरित करें।

/

/

/

/

/

आपराधिक मूल न्यायनिर्णय: 2019 की स्थानांतरण याचिका (आपराधिक) No.125।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 406 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 139 ए (2) के अंतर्गत स्थानांतरण याचिका 2016 के एस. सी. No.285 वाले मामले के हस्तांतरण के लिए प्रार्थना करती है जो ए.

/

1105

1106

/

[2023] 1 एस सी आर।

भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 148,149,186,302,307,435,436,439,335,323,326 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 के अंतर्गत अतिरिक्त न्यायालय के समक्ष लंबित "हरियाणा राज्य बनाम संदीप @काला और ए. एन. आर". शीर्षक वाले मामले में पुलिस स्टेशन-झज्जर में दर्ज प्राथमिकी। सत्र न्यायाधीश, झज्जर से नई दिल्ली में सक्षम न्यायालय में]

/

अभिमन्यु तिवारी, नीकेतो रियो, सुश्री एलिजा बार, अधिवक्ता। याचिकाकर्ताओं के लिए।

निखिल गोयल, ए. ए. जी., डॉ. जोसेफ अरस्तू, आदित्य सिंह, शुभम सिंह, राजीव दलाल, पंकज यादव, अनिरुद्ध देशमुख, आदित्य के. राँय, नवीन गोयल, सुश्री मोनिका गुसैन, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए। न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्णय दिया गया था:

/

निर्णय

(1) स्थानांतरण याचिका में मांगी गई राहत इस प्रकार है:“(क) भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 148,149,186,302,307,435,436,449,395,323,326 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 से उत्पन्न 2016 के एस. सी. No.116 वाले मामले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, झज्जर की न्यायालय के समक्ष लंबित "हरियाणा राज्य बनाम संदीप @काला और अन्य" शीर्षक से पुलिस स्टेशन-झज्जर को नई दिल्ली के सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित कर दें। ”

/

/

(2) याचिकाकर्ताओं का मामला संक्षेप में यह है कि 2016 में हरियाणा राज्य में जाट समुदाय के सदस्यों द्वारा एक आंदोलन किया गया था। उन्होंने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मांग की। इस आंदोलन के दौरान, जाट समुदाय के सदस्यों ने तोड़फोड़ की और

आगजनी की, जिससे कथित तौर पर याचिकाकर्ताओं के घरों, गोदामों और उनके हर सामान में आग लगाकर उन्हें भारी अपूरणीय क्षति पहुंची।

/

(3) एक वकील के खिलाफ आरोप लगाया जाता है, जिस पर बहुत प्रभावशाली होने का आरोप लगाया जाता है और जो बार का अध्यक्ष बना रहा। यह आरोप लगाया जाता है कि इस मिलीभगत के कारण, 2-3 भौतिक गवाहों को शत्रुतापूर्ण होने के लिए मजबूर किया गया है और साथ ही सामग्री दस्तावेजी साक्ष्य को रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है।

/

(4) यह उनका आगे का मामला है कि अधिवक्ता और उनके बेटे को समन करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया गया था, लेकिन उनके आवेदन पर ए द्वारा जवाबी हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

/

1107

सुनील सैनी एंड ओआरएस. वी.हरियाणा और ओआरएस का राज्य।

लोक अभियोजक।इसलिए याचिकाकर्ताओं ने अपने मामले को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए यह याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया ताकि न्याय के हित को कम किया जा सके।

(5) प्रतिवादी संख्या 2 और 2 द्वारा जवाबी शपथपत्र के साथ-साथ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है।3. अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए आवेदन में, यह स्थापित करने की मांग की गई है कि वास्तव में, इस न्यायालय के समक्ष पहले याचिकाकर्ता से पीडब्लू-2 के रूप में पूछताछ की गई थी और उसने अपने बयान में कहा है कि वह यह पहचान नहीं कर सका कि आरोपी कौन हैं।पीडब्लू-15 कथित तौर पर एक आरोपी की पहचान कर रहा था। पीडब्लू-15 के कहने पर, कुछ व्यक्तियों (विचाराधीन अधिवक्ता) को समन करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता धारा 319 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे खारिज कर दिया गया है।

/

/

(6) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील, वास्तव में, प्रस्तुत करेंगे कि धारा 319 के अंतर्गत आवेदन को खारिज करने के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है।याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील यह इंगित करेंगे कि यह एक सकल मामला है जहां विधि और व्यवस्था पूरी तरह से टूट गई है जिसके परिणामस्वरूप भारी नुकसान हुआ है।यह भी बताया गया है कि दो लोगों की जान

चली गई।(7) यह उनका मामला है कि प्रश्न समुदाय के व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं को हरियाणा राज्य के न्यायालयों में न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है।इसके अलावा, अभियोजन दल भी निष्पक्ष और निडर तरीके से काम नहीं कर रहा है।(8) आज तक, यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि 42 गवाहों से पूछताछ की गई है।याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील यह इंगित करेंगे कि इस स्तर पर, कम से कम यह न्यायालय यह निर्देश देने पर विचार कर सकता है कि एक स्वतंत्र और ईमानदार विशेष अभियोजक नियुक्त किया जाए ताकि आवश्यक कार्य किया जाए और कार्यवाही में कोई तोड़फोड़ न हो।वह प्रस्तुत करेगा कि उन गवाहों को वापस बुलाने के लिए एक मामला मौजूद हो सकता है जिनसे पहले ही पूछताछ की जा चुकी है।

/

/

/

(9) दूसरी ओर, प्रथम प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील इंगित करेंगे कि लोक अभियोजक को 13.05.2022 पर नियुक्त किया गया है।वह वह व्यक्ति है जो 29.03.2003 के बाद से लोक अभियोजक रहा है और उसने भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत लगभग 500 मामले, आंदोलन से उत्पन्न होने वाले दो मामले और ऑनर किलिंग के दो अन्य मामले भी चलाए हैं।इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बताया गया है कि लोक अभियोजक के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं जिन्हें उपरोक्त के रूप में नियुक्त किया गया है।

/

/

1108

/

[2023] 1 एस सी आर।

/

(10) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने एक और शिकायत भी उठाई है।यह बताया गया है कि नियमित रूप से, याचिकाकर्ता जो गवाह हैं, उन्हें दूसरे पक्ष द्वारा धमकान्तर्गत दी गई है।उन्होंने कहा कि अनुरोध किए जाने के बावजूद सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है।

(11) दूसरी ओर, प्रथम प्रतिवादी-राज्य के लिए विद्वान वकील बताते हैं कि एक गवाह संरक्षण योजना, 2018 है।एक गवाह जिसे डराया जाता है, उसे हमेशा पीठासीन न्यायाधीश या लोक अभियोजक या संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को लिखने का अधिकार होगा।सुनवाई की अंतिम तिथि पर केवल एक अनुरोध प्राप्त हुआ है, इसे प्रस्तुत किया जाता है।

/

/

(12) जहाँ तक मामले को राज्य से बाहर स्थानांतरित करने का संबंध है, हम सोचेंगे कि समय बीतने और इस तथ्य के कारण कि लगभग 42 गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है, हम नहीं सोचते कि, जैसा कि मामला है, मामले को स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

(13) हमें यहाँ एक पल के लिए रुकना चाहिए और हालाँकि ये टिप्पणियाँ करनी चाहिए:

/

राज्य का अस्तित्व शासित की निहित सहमति के आधार पर होता है। राज्य के संगठन के अंतर्गत लोगों के एक साथ आने का प्रमुख कारण यह मौलिक सिद्धांत है कि राज्य हमेशा नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने की स्थिति में रहेगा। यह किसी भी सभ्य राज्य के निर्माण, अस्तित्व और संरक्षण के लिए मौलिक अपरिवर्तनीय आधार है। यह और भी अधिक तब होता है जब राज्य एक लिखित संविधान के अंतर्गत काम कर रहा होता है जो हमारे जैसे मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। तदनुसार विधि के शासन को संविधान की मूल संरचना के हिस्से के रूप में उचित रूप से माना जाता है। यह सुनिश्चित करना किसी भी राज्य का परम कर्तव्य है कि उसके नागरिकों और अन्य व्यक्तियों के जीवन की हर समय रक्षा की जाए। यही बात उनकी संपत्तियों पर भी लागू होती है। यह राज्य का प्राथमिक कार्य है। हमें इस स्तर पर राज्य के कर्तव्यों से निपटने के लिए नहीं कहा गया है, जिस पर कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी आती है। यदि राज्य के गठन के लिए यह अपरिहार्य कार्य भी पूरा नहीं किया जाता है, तो भी यह एक दुखद स्थिति होगी।

/

/

/

(14) विधि के शासन को सही साबित करने और नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए प्रमुख तंत्र राज्य की न्यायिक शाखा है। मौलिक विधियों में से एक जिसके द्वारा विधि के शासन को संरक्षित किया जाता है, उसमें प्रतिबंध शामिल हैं जिनमें से आपराधिक विधि एक है।

/

1109

सुनील सैनी और ओआरएस बनाम हरियाणा और ओआरएस का राज्य।

प्रमुख शाखा। आपराधिक अदालतों को इस तरह से काम करने की अनुज्ञात जानी चाहिए जिसके द्वारा दिन के अंत में दोषियों को दंडित किया जाए और निर्दोष को दोषमुक्त किया जाए।

(15) इन सब में लोक अभियोजक की भूमिका सर्वोपरि है। वह हमेशा निशुल्क तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य है; निश्चित रूप से, हुक या क्रूक द्वारा दोषसिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि साथ

ही, यह उसका कर्तव्य है कि वह निडरता से सबूत पेश करे ताकि जो दोषी हैं वे बच न सकें। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, तब तक इस बात की बहुत संभावना है कि आम आदमी का राज्य के कामकाज में ही विश्वास नहीं रहेगा। इसलिए, यह राज्य की अखंडता को बनाए रखने के लिए अभिन्न है कि न्याय तक पहुंच जो इस सिद्धांत में भी समझी जाती है कि राज्य के खिलाफ अपराध किया जाता है और इसलिए राज्य अपराधी पर मुकदमा चलाता है, हमेशा ध्यान में रखा जाता है। (16) हर वह प्रयास जो किसी के हाथों सफल होता है जिससे आपराधिक विधि की प्रभावशीलता कम हो जाती है, विधि के शासन की इमारत को घातक रूप से हटा देगा।

/

/

/

(17) इसलिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विशेष लोक अभियोजक, जिसे नियुक्त किया गया है, उम्मीद है कि उच्चतम सिद्धांतों को बनाए रखेगा और कठिन भूमिका निभाएगा ताकि निर्दोष को दोषी नहीं ठहराया जाए, लेकिन दोषी उचित सजा से न बच सकें।

/

(18) इस मामले के तथ्यों में, यह देखते हुए कि विशेष लोक अभियोजक को हाल ही में नियुक्त किया गया है और उसकी साख के बारे में भी बेपरवाह नहीं है जो हमारे ध्यान में लाया गया है, इस स्तर पर हम यह निर्देश देने के लिए राजी नहीं हैं कि उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। हालाँकि, यह इस मामले की नियति का अंत नहीं है। तदनुसार, हम याचिका का निपटारा इस प्रकार करते हैं:

/

(i) याचिकाकर्ताओं के लिए यह खुला रहेगा कि वे अभियोजन निदेशक से संपर्क करें यदि उन्हें लगता है कि नियुक्त विशेष लोक अभियोजक भी निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है।

/

(ii) यह निदेशक (अभियोजन) पर है कि वह मामले को देखे और उचित कदम उठाए। जहाँ तक गवाह के संरक्षण का संबंध है, याचिकाकर्ताओं के लिए पीठासीन न्यायाधीश या विशेष लोक अभियोजक या संबंधित के पुलिस अधीक्षक के पास जाने की अनुमति होगी।

/

[2023] 1 एस सी आर।

/

जिस मामले में आवश्यक सुरक्षा की मांग करने वाला जिला विधि के अनुसार किया जाएगा।

((ग) यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस निर्णय में हमने जो भी अवलोकन किया है, वह साक्ष्य के आधार पर और लागू विधि के आधार पर निर्णय लेने के न्यायालय के रास्ते में खड़ा नहीं होगा।

/

स्थानांतरण याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

निधि जैन

स्थानांतरण याचिका का निपटारा किया गया।

(सहायक: शाश्वत जैन, एलसीआरए)

/

/

/

/

/

/